राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय है जेएनयू

किसी भी देश के शैक्षणिक संस्थानों का रंग-रूप आमतौर पर वैसा ही होता है जैसी वहां की सरकार होती है। शैक्षणिक परिसर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार की नीतियों के प्रथम प्रवक्ता होते हैं। देश में सरकार बदलने के साथ ही शिक्षा संस्थानों को बदलने की जो मुहिम शुरू हुई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उसके केंद्र में रहा है। सरकार के साथ राष्ट्रवादी बहस को भी तीन साल हो गए हैं। अभी कैसा और क्यों है जेएनयू, बारादरी की बैठक में इसी मसले पर बातचीत की कुलपति एम. जगदीश कुमार ने। कार्यक्रम का संचालन किया कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने।

बारादरी की बैठक में एम. जगदीश कुमार

सभी फोटो: आरुष चोपड़ा

राजेंद्र राजन: शिक्षा के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, मगर जब उच्च शिक्षा में बेहतरीन विश्वविद्यालयों की सूची जारी होती है तो यहां के इक्का-दुक्का संस्थान ही उसमें जगह बना पाते हैं। इसकी क्या वजह है?

एम. जगदीश कुमार: इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो वर्ल्ड रैंकिंग, इसमें जो मानदंड इस्तेमाल किए जाते हैं, वे हमारे पक्ष में नहीं हैं। विश्वविद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है-उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना। भारत में अगले दस सालों में तीस करोड़ युवकों को शिक्षित करना पड़ेगा। यह हम कैसे कर पाएंगे? फिलहाल हमारे यहां आठ सौ विश्वविद्यालय और चार हजार कॉलेज हैं। नैक की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से अधिकतर विश्वविद्यालय और कॉलेज औसत से भी नीचे हैं। इसलिए हमारा प्राथमिक उद्देश्य दुनिया के विश्वविद्यालयों की सूची में आना नहीं है। जब हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, तो अपने आप अच्छे विश्वविद्यालयों की सूची में भी आएंगे।

रामजन्म पाठक: जेएनयू में एमफिल, पीएचडी की सीटें काफी घटा दी गई हैं, ऐसे में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित कर पाना कैसे संभव होगा?

एम. जगदीश कुमार: जहां तक जेएनयू में सीटें कम करने का सवाल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। यूजीसी ने 2009 में कहा था कि एमफिल और पीएचडी में हर प्रोफेसर के लिए तय सीटों से ज्यादा विद्यार्थी नहीं लिए जाने चाहिए। इसमें एक प्रोफेसर के लिए आठ विद्यार्थी निर्धारित हैं। मगर जेएनयू ने उसे लागू नहीं किया। बाकी सभी विश्वविद्यालयों

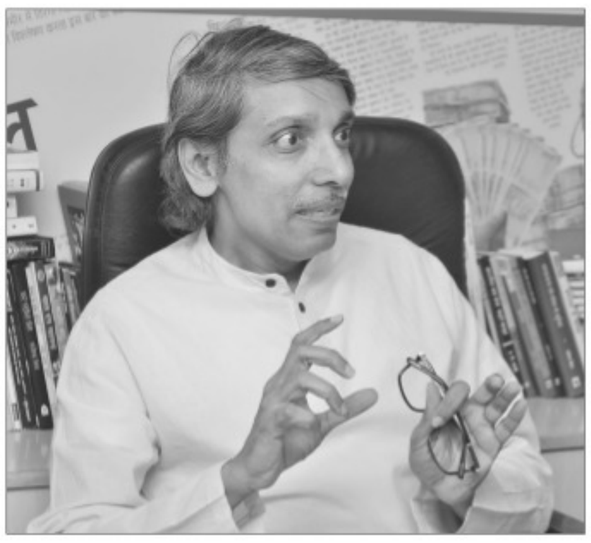

ने लागू किया। हालांकि, एक प्रोफेसर पर आठ विद्यार्थी भी ज्यादा संख्या है। दुनिया के जिन अच्छे विश्वविद्यालयों की बात हो रही थी, वहां तीन-चार से ज्यादा नहीं होते। लेकिन हमारे जेएनयू में तीस-चालीस विद्यार्थी मिल जाएंगे। पीएचडी ऐसे नहीं कराई जा सकती। इसलिए पिछले साल हमने यूजीसी के उस निर्देश को लागू किया। पर लोगों को लग रहा है कि सीटें कम हो गईं।

जहां तक दाखिलों का सवाल है यूनीवर्सिटी को हमें बाउंड्रीलेस बनाना होगा। दूर-दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देंगे? जेएनयू से लेक्चर रिकार्ड करके हम ऑनलाइन डाल सकते हैं, जिससे दूर-दराज गांवों के बच्चे पढ़ सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल में इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू भी किया है- ई-पाठशाला। इस तरह हम पारंपरिक पढ़ाई को बदल सकते हैं। जेएनयू में भी हम अध्यापकों और दूसरी एजंसियों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं कि किस तरह ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है।

रूबी कुमारी: कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि हमें अकादमिक गुणवत्ता के बजाय सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर बढ़ना है। लेकिन इन दिनों जिस तरह जेएनयू में वैचारिक टकराव बढ़ गया है, उससे नकारात्मक छवि बन रही है।

एम. जगदीश कुमार: जेएनयू में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रोफाइल देखिए तो पता चलेगा कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत कमजोर तबके से आए हैं। हमारा लक्ष्य इन लोगों को इस तरह तैयार करना है कि वे यहां से निकल कर जाएं और समाज में कुछ बेहतर योगदान करें। अभी भारत में हम हर साल दस लाख लोगों को इंजीनियर बनाते हैं, मगर उनमें से केवल दस फीसद को रोजगार दे पाते हैं। विश्वविद्यालयों का ध्यान हमेशा इस बात पर रहना चाहिए कि किस तरह नया पाठ्यक्रम शुरू करें, नया रिसर्च शुरू करें। जहां तक वैचारिक टकराव की बात है, मेरा मानना है कि एक विद्यार्थी होने के नाते उसे अपने समाज को बारीकी से देखना चाहिए। इसलिए जब हम समाज पर नजर रखते हैं, तो वहां अच्छा या बुरा जो कुछ हो रहा होता है, उसे देख कर हम अपना एक विचार बनाएंगे ही। यह उम्र ही बहसतलब होने की होती है। अपने विचार में रद्दोबदल करते हैं। और यह भी स्वाभाविक है कि मेरे पास एक विचार है और दूसरे के पास दूसरे तरह का विचार है तो वे दोनों कहीं न कहीं टकराएंगे। पर इस टकराव से एक सर्वस्वीकृत विचार पैदा होता है। यह स्वाभाविक है और इसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। हम चाहते हैं कि भिन्न-भिन्न विचारों के लोग हों और वे खुल कर आपस में बहस-मुबाहिशा करें। और हर विचार को सुना जाना चाहिए।

मृणाल वल्लरी: आपके कार्यकाल में जेएनयू प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव कुछ अधिक देखा जा रहा है, इसकी क्या वजह है?

एम. जगदीश कुमार: कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, जहां प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव न होता हो। और यह विद्यार्थियों का अधिकार है कि वे प्रशासन से अलग मत रखें।

रूबी कुमारी: मगर छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर होने के बाद से स्थितियां ज्यादा तनावपूर्ण हो गई हैं।

एम. जगदीश कुमार: किसने देशद्रोह का मुकदमा कराया। नौ फरवरी को जो कुछ हुआ उस पर मैंने तो यही कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे हम खुद सुलझाएंगे। जो जेएनयू के बाहर हुआ, उस पर हमारा नियंत्रण तो नहीं है।

मुकेश भारद्वाज: एक आम धारणा है कि जेएनयू में वामपंथ का दबदबा रहा है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए अब उसका भगवाकरण करने का प्रयास हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?

एम. जगदीश कुमार: देखिए, चाहे वह वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, हम सभी देश के लिए काम करते हैं। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर हम साथ मिल कर कहीं न कहीं समाज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि हर विचारधारा का स्वागत होना चाहिए। हमारे यहां छह सौ से ऊपर अध्यापक हैं और करीब आठ हजार सात सौ विद्यार्थी हैं, आप उनमें से किसी से भी पूछिए, कोई नहीं कहेगा कि वह कानून तोड़ना चाहता है। हर कोई देश के लिए काम करना चाहता है। बेशक उनके बोलने और काम करने के तरीके में भेद हो सकता है। इसलिए जेएनयू हर विचारधारा का स्वागत करता है। जेएनयू में शायद ही कोई ऐसा हो, जो कहे कि वह राष्ट्रद्रोही है। इसलिए जेएनयू राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय है।

अरविंद शेष: आपके अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है?

एम. जगदीश कुमार: अभी हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे पार पाने के लिए हम अपने विद्यार्थियों को किस तरह तैयार करें, किस तरह रोजगार के अवसर पैदा करें, किस तरह बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें, कैसे गांव के लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, एक शिक्षक के नाते हमारी चिंता यह है और एक विद्यार्थी के नाते भी हर किसी की होनी चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों के सामने अभी यह चुनौती है कि इन तमाम समस्याओं को अपने अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामने रखें। हम अपने प्रयासों से किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, मेरे हिसाब से यही राष्ट्रवाद है।

सुशील राघव: नियुक्तियों के मामले में जेएनयू की अपेक्षा दिल्ली के दूसरे विश्वविद्यालयों में स्थिति बेहतर है। इस दिशा में क्या करने वाले हैं?

एम. जगदीश कुमार: जेएनयू में बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि विभिन्न एजंसियों से संपर्क करके अपने विद्यार्थियों के बेहतर प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हाल ही में हमने एक प्लेसमेंट सेल गठित किया है। एक प्रोफेसर को इसका निदेशक बनाया गया है और हर स्कूल से तालमेल करके विभिन्न संस्थाओं-एजेंसियों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा संभव है कि अगले साल तक हमें इस मामले में काफी सफलता मिलेगी।

अभी हम जेएनयू में एक इंजीनियरिंग का नया स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं। जेएनयू बेसिक रिसर्च के लिए जाना जाता है। अगर इंजीनियरिंग स्कूल खुलेगा तो बेसिक रिसर्च के आधार पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। फिर एक स्कूल ऑफ एंटरप्रोन्योर एंड मैनेजमेंट भी खोलने की जरूरत है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इन स्कूलों में हम थोड़े अलग ढंग से काम करना चाहेंगे। इनमें अनौपचारिक रिसर्च को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी गांव में कोई इन्नोवेशन किया, तो उसे हम बढ़ावा देंगे। देश में हजारों ऐसे इन्नोवेटर हैं, जिनके काम को इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं मिल पाता। जेएनयू उन्हें बढ़ावा देगा। उन्हें प्रशिक्षित करने का भी प्रयास होगा।

प्रियरंजन: पिछले दिनों कई ऐसे फैसले हुए, जिनमें जेएनयू को अपने कदम वापस खींचने पड़े। पहले ही इसकी तैयारी क्यों नहीं कर ली जाती कि ऐसी स्थिति आने ही न पाए?

एम. जगदीश कुमार: हमारे यहां कई ऐसी बॉडी हैं, जिनका आपस में विचार-विमर्श होता रहता है। मगर जहां तक यूजीसी गजट नोटीफिकेशन की बात है, वह 2016 में आया था। यूजीसी गजट नोटीफिकेशन को लागू करना अनिवार्य होता है। इसलिए जब मैंने एकेडेमिक काउंसिल से बात की तो उन्होंने कहा कि हां, हम इसे लागू कर सकते हैं। यूजीसी ने साफ कहा था कि एमफिल और पीएचडी में दाखिले के लिए दो स्तरों पर परीक्षा ली जा सकती है। पहले लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में रिसर्च आधारित पाठ्यक्रमों में दाखिला सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होता है। यहां तक कि विदेशी संस्थानों में भी एमफिल-पीएचडी में दाखिला सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होता है। इसलिए हम लोग बहुत अलग नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे भी कार्यक्रम हैं- बीए, एमए। हमने उनमें दाखिले की प्रक्रिया नहीं बदली है। बदलाव सिर्फ एमफिल-पीएचडी में हुआ है।

सुशील राघव: जेएनयू बहुत से विद्यार्थी का सपना होता है। सीटें खत्म होने से उन्हें बहुत निराशा होगी। क्या उन्हें एक साल इंतजार करना पड़ेगा? जेएनयू इसके लिए क्या कर रहा है?

एम. जगदीश कुमार: हमने अपने शिक्षकों से कहा है कि आपके साथ जो वर्षों से तीस-चालीस विद्यार्थी काम कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से काम पूरा करने को कहिए, ताकि नए विद्यार्थियों को जगह मिल सके। एकेडमिक काउंसिल में तय किया है कि इस साल इंटरव्यू दिसंबर में ही कर लेंगे। जुलाई तक इंतजार नहीं करेंगे। फिर हमने यह भी कहा है कि देखें कि किस प्रोफेसर के पास अधिकतम विद्यार्थी हैं। अभी हमने नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए अध्यापक आएंगे तो विद्यार्थियों के लिए अपने आप जगह बनेगी। एक साल के भीतर हम अधिक विद्यार्थियों को दाखिला दे सकेंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है।

जेएनयू हर विचारधारा का स्वागत करता है। जेएनयू में शायद ही कोई ऐसा हो, जो कहे कि वह राष्ट्रद्रोही है। इसलिए जेएनयू राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय है। हम चाहते हैं कि जेएनयू का हर अध्यापक और विद्यार्थी समाज की बेहतरी के लिए काम करे।

पारुल शर्मा: आपने जेएनयू में वॉल ऑफ हीरोज बनाई है, उसकी क्या जरूरत पड़ गई?

एम. जगदीश कुमार: वहां सिर्फ हमारे सेना के शहीदों की तस्वीरें लगी हैं। उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी गंवाई है, तो उनके त्याग को याद करने के लिए इतना तो करना बनता है। उनके प्रति सम्मान जाहिर करने के मकसद से ऐसा मैंने किया।

सूर्यनाथ सिंह: आप पर सरकार का कितना दबाव है?

एम. जगदीश कुमार: कोई दबाव नहीं है। मुझे पूरी आजादी है।

रूबी कुमारी: उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए तो आपने जो ट्वीट किया, उस पर काफी विवाद हुआ। एक कुलपति के रूप में वैसा ट्वीट कितना उचित था?

जगदीश कुमार: कुलपति आम नागरिक से अलग नहीं है। ऐसा ट्वीट करने का अधिकार सबको होना चाहिए। आप दुबारा मेरा ट्वीट पढ़िए, उसमें यूपी चुनाव का कोई जिक्र है क्या?

राजेंद्र राजन: विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने अपने कैंपस खोलने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं?

एम. जगदीश कुमार: अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा देने की जरूरत है। अगर हम उन्हें शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? बच्चे बैंक से लोन लेंगे और पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे। वह पैसा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रक्रिया को कम किया जाए। भारत में नए विश्वविद्यालयों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। उद्योगपति पैसा लगा कर खोल सकते हैं, कोई विदेशी विश्वविद्यालय आकर खोलना चाहे तो खोल सकता है। मगर उसका मकसद अच्छी शिक्षा देना होना चाहिए, न कि पैसा बनाना।

प्रस्तुति: सूर्यनाथ सिंह / मृणाल वल्लरी

जनसत्ता बारादरी

एम. जगदीश कुमार क्यों

देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च शैक्षणिक परिसर को पूरी तरह राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है। एक खास रंग से प्रभावित होने के आरोप में दूसरे रंग से वैचारिक पुताई करने के आरोप लगे, जिसका असर नियुक्तियों, दाखिलों और प्रशासन के ढांचे पर भी दिखने लगा। कई मंचों से गुणवत्ता का पुरस्कार हासिल कर चुका संस्थान अपना सब कुछ बदलने पर आमादा क्यों है? इन सवालों के जवाब तो संस्थान के अगुआ ही दे सकते हैं।

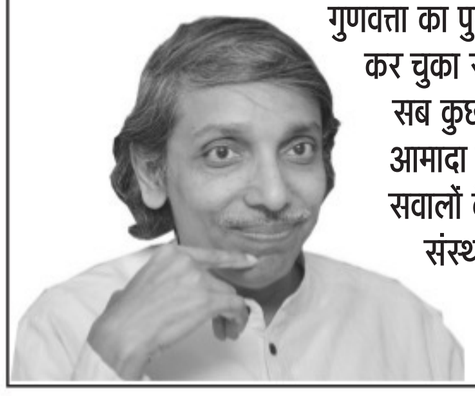

लालमुनिया, घोंसला कहां बनाओगी

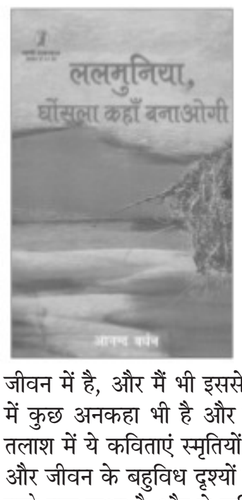

आनंद वर्धन गंवई संवेदना के कवि हैं। उनकी कविताओं में उनका गांव-जवार धड़कता है, वहां की बोली-बानी, रीति-रिवाज सहज भाव से उतर आते हैं। शहर में रमते हुए भी वे वहां एक गांव तलाश लेते हैं। वहां के श्रमिकों-मजदूरों में गांव को धड़कता महसूस करने लगते हैं। वे रोजमर्रा की जिंदगी से अपने विषय चुनते और उन्हीं से बिंब रचते हैं। हर जगह आम आदमी की जद्दोजहद और उसकी औसत जिंदगी का लेखा-जोखा उनकी कविताएं पेश करती हैं। जहां कवि सैलानी बन कर घूमने जाता है, वहां भी उसे चमक-दमक और प्राकृतिक सौंदर्य के बजाय आम लोगों के संघर्ष अधिक दिखाई देते हैं।

आनंद वर्धन स्वीकार करते हैं कि 'हमारे चारों ओर जो कुछ भी बिखरा है, फैला है, पसरा है और घटता रहता है, वह सब कुछ हमें एक ऊर्जा भी देता है और दृष्टि-संपन्न भी बनाता है। यह बहुत कुछ सबके जीवन में है, और मैं भी इससे अलग नहीं हूं। गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि इस बहुत कुछ में कुछ अनकहा भी है और वह अपनी उपस्थिति पाता है कविता की संरचना में।... कुछ खोजने की तलाश में ये कविताएं स्मृतियों से लेकर समुद्र की हवाओं, जंगलों से लेकर गांव और खेतों तक जाती हैं और जीवन के बहुविध दृश्यों को स्पर्श करती चलती हैं। जीवन की अनेक छवियों ने मन को कहीं-कहीं गहरे तक छुआ है और वे छवियां शब्दों के माध्यम से प्रतिकृति के रूप में ढल कर उपस्थित हुई हैं।'

ललमुनिया, घोंसला कहां बनाओगी: आनंद वर्धन; वाणी प्रकाशन, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 200 रुपए।

किताबें मिलीं

शहादत

राजेंद्र मोहन ने आधुनिक इतिहास के नायकों के जीवन को आधार बना कर कई उपन्यास लिखे हैं। इतिहास को कथा में ढालना खासा जोखिम भरा काम होता है, पर भटनागर ने वह जोखिम बखूबी उठाया और इतिहास को कथा रूप में पेश करने का प्रयास किया है। उनकी यह नई किताब भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। यह इंदिरा गांधी के सड़सठ सालों के उथल-पुथल भरे, घटनापूर्ण जीवन की गाथा है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि एक संकोची, एकांत पसंद, गुमसुम रहने वाली लड़की में ऐसी कौन-सी विलक्षणताएं थीं जिनके कारण वह दो बार देश की प्रधानमंत्री चुनी गई।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश के जन्म, इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से जहां इंदिरा गांधी की छवि एक दबंग, निष्ठुर नेता की थी वहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में वे संवेदनशील, कला और संस्कृति की परख रखने वाली, जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने वाली महिला और ममतामयी मां थीं। उनके जीवन के इन सभी पहलुओं को एक साथ बुन कर लेखक ने एक रोचक और पठनीय जीवनी का सृजन किया है। इस बहाने तत्कालीन राजनीति को जानने-समझने का मौका भी मिलता है।

शहादत: राजेंद्र मोहन भटनागर; राजपाल एंड सन्ज, 1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली; 395 रुपए।

स्त्री दशा और दिशा

आभा सिंह और नसीम अंसारी कोचर की यह किताब सिर्फ स्त्रियों पर होने वाले जुल्म की दास्तान नहीं है। इसमें महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, बलात्कार, मानसिक-शारीरिक शोषण का ब्योरा और आंकड़े भर नहीं हैं। यह उन तमाम कारणों की पड़ताल करती है, जिनके चलते समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। इनमें एक बड़ा कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। हर जगह पुरुष का वर्चस्व कायम है। महिलाओं को न सिर्फ शारीरिक, बल्कि मानसिक स्तर पर भी कमजोर मानने की मानसिकता बनी हुई है। इसलिए उसके साथ भेदभाव बंद नहीं होता। यह मानसिकता पढ़े-लिखे और साधन संपन्न वर्ग में भी खूब देखी जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि निचले वर्गों में महिलाओं की क्या स्थिति होगी। इस तरह यह किताब उन वर्गों की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के मकसद से भी लिखी गई है। समाज के सभी वर्गों और समुदायों की स्त्रियों की दशा और दिशा का विश्लेषण किया गया है। तमाम समुदायों में स्त्रियों के प्रति हुए अत्याचारों का विवरण देते हुए समस्या की गंभीरता को दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें अनेक पीड़ित स्त्रियों से बातचीत करके उनके अनुभव बटोरने का भी प्रयास किया गया है। कहानी के शिल्प में लिखी गई इस किताब की भाषा अत्यंत सहज-सरल और प्रवाहमयी है, इसलिए ज्यादा प्रभावोत्पादक भी।

स्त्री दशा और दिशा: आभा सिंह, नसीम अंसारी कोचर; रणसमर फाउंडेशन, 1501 हरिसिद्ध हाइट्स, राइफल क्लब के सामने, वर्ली सर्कल, वर्ली सीफेस, मुंबई; 250 रुपए।